

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 33/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

जे. एम. फाइनेंसियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी
जगदीश मीणा

कार्यालय:- सातवीं मंजिल, सिनर्जी, अप्पा साहिब मराठे मार्ग, प्रभा देवी, मुंबई,
महाराष्ट्र-400025

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. धर्मवीर सिंह तंवर पुत्र सुरेन्द्र सिंह तंवर निवासी रीको एरिया जलपाली
श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर 332715

2. सुरज्ञान कंवर पत्नी धर्मवीर सिंह

प्रथम पता:- वार्ड न. 8 हरदास का बास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
राजस्थान 332707

द्वितीय पता:- दुकान व मकान न. 83/5650 खसरा न. 312/1 ग्राम भारनी
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. 332715

-अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

**The application under section 14 of the securitisation and reconstruction
of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.**

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 20 अप्रैल, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री कंचन सिंह चौधरी द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः धर्मवीर सिंह तंवर पुत्र सुरेन्द्र सिंह तंवर व सुरज्ञान कंवर पत्नी धर्मवीर सिंह की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



स्वामित्व की अचल सम्पत्ति दुकान व मकान न. 83/5650 खसरा न. 312/1 ग्राम भारनी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. 332715 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 61.63 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उत्तर दिशा में सड़क, दक्षिण दिशा में विजय सिंह का मकान, पूरब दिशा में रास्ता व पश्चिम दिशा में विजय सिंह का मकान स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल ₹9,50,000/- रुपये (अक्षरे रुपये नौ लाख पचास हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 21.11.2024 के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 21.11.2024 को धारा 13(2) के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।




(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः धर्मवीर सिंह तंवर पुत्र सुरेन्द्र सिंह तंवर व सुरज्ञान कंवर पत्नी धर्मवीर सिंह की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति दुकान व मकान न. 83/5650 खसरा न. 312/1 ग्राम भारनी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. 332715 में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 61.63 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— उत्तर दिशा में सड़क, दक्षिण दिशा में विजय सिंह का मकान, पूरब दिशा में रास्ता व पश्चिम दिशा में विजय सिंह का मकान स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के स्वीकृति आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।



6. आदेश आज दिनांक 20 अप्रैल, 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर